वस्तुओं के अतिरिक्त और अधिक उपभोक्ता वस्तुओं को बिक्री किये जाने हेतु प्रबन्ध किये जाने का विचार रखती है?

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) कुछ चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में पिछले छः महीनों के दौरान एक मिला जुला रुख रहा है। कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चना, चाय, चीनी, गुड़, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चावल, ज्वार, अरहर, मूंग, मिर्च, नारियल का तेल और आलू की कीमतों में गिरावट हुई तथा मिट्टी का तेल और सॉफ्ट कोक की कीमतें यथावत रही हैं।

(ख) से (घ) इस समय सात बुनियादी वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल साफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़ा केन्द्रीय सरकार द्वारा इंसिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुकानों के जरिए पूर्ति हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों को दिया जाता है समय-समय पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती रही है कि वे स्वयं भी जन-उपभोग की अधिक से अधिक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए स्थानीय स्थितियों के आधार पर उपलब्ध करायें। दालें, चाय, दियासलाई, नमक, साइकिल टायर, साबुन, मोटे अनाज इत्यादि जैसी अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण भी कुछ राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।

सभी के लिए शिक्षा

174. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "वर्ष 2,000 तक सभी के लिए शिक्षा" का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि इस दिशा में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह परिकल्पना की गयी है कि वे सभी बच्चे जो वर्ष 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा के जरिए पांच वर्षों अथवा इसके बराबर की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली होगी। इसी तरह वर्ष 1995 तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

(ख) से (घ) पढ़ाई बीच में छोड़ कर जाने वाले बच्चों की समस्या की ओर ध्यान देने और देश भर में बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के प्रयास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियां अपनाने संबंधी नीति के अनुसरण में वर्ष 1987–88 से कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरु की गयी हैं ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में अभिवृद्धि की जा सके। मुख्य योजनाएं ये हैं : (i) देश भर में एकल शिक्षक वाले सभी स्कूलों में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था, कम से कम दो कक्षों वाले भवन की व्यवस्था और प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को अनिवार्य शिक्षण-अध्ययन सामग्रियों के सैट की व्यवस्था के द्वारा भौतिक सुविधाओं के सुधार के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड। (ii) स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों तथा कामकाजी बच्चों के लिए जो पूरे दिन स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते अनौपचारिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त कई व्यापक कार्यक्रम और

(iii) शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों को सतत सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं हेतु योजना।

इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को निम्नलिखित राशि पहले ही दी जा चुकी है।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	अनौपचारिक शिक्षा	शिक्षक शिक्षा
1987-88	110.71	38.04	47.87
1988-89	135.73	36.92	50.00

आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत 253279 स्कूलों को शामिल करने, 2.4 लाख नए औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने और 216 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को प्रारम्भ करने के लिए संस्वीकृति जारी की जा चुकी है।

शिक्षा के विकास आदि के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मांगी गई धनराशि

175. **श्री राम नरेश यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद आदि के लिए 45,000 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त मांग पर विचार किया है; है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन): (क) जी, नहीं। तथापि, योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित शिक्षा के लिए संसाधन (कला, संस्कृति तथा युवा कार्य और खेल सहित) सम्बंधी कार्य दल ने यह अनुमान लगाया था कि इस कार्य के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 45,000 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी आयोजना मंत्री को भी लिखा था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अन्तर-क्षेत्रीय आबंटनों को अन्तिम रूप देते समय लिया जाएगा।

Increase in the prices of sugar

176. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA;

Will the Minister of FOOD AND CIVIL. SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of sugar have risen in recent days in different States, ranging from Rs. 11 to Rs. 17 a kilo; and

(b) if so, what steps are being taken by Government to reduce the prices of sugar?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES **(SHRI NATHU RAM MIRDHA):** *[(a)* **and '(b) The** retail prices of sugar in the open market had increased abnormally high during the month July to September, 1989. The retail markets prices of free sale sugar, which were in the ■range of Rs. 10.00—Rs. 13.00 per kg. in September, 1989, and Rs. 9.00—Rs. 10.50 per kg. in the beginning of December 1989 have been brought down in the range of Rs. 7.30—Rs. 8.75 per kg. in the most of the important markets in the country. The Government has issued strict directions to the factories to comply with the statutory provisions relating to sale and despatch of minimum 20% free sale sugar quota for a month during